



नैनीताल हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे आर.बी. मल्लिक
संवाददाता देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के नाम पर फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा लिए गये फैसले के अनुसार आर.बी.मल्लिक की नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति होगी, जो नैनीताल हाईकोर्ट के 11वें चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान में आर.बी. मल्लिक कर्नाटक हाईकोर्ट में जज के पद पर कार्यरत हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी गयी है। आर.बी. मल्लिक वर्तमान कर्नाटक हाईकोर्ट में जज के पद पर कार्यरत हैं जो नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रांगनाथन की जगह पदभार संभालेंगे। जो दो नवम्बर 2019 से नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर आसीन है। आर.बी. मल्लिक नैनीताल हाईकोर्ट के 11वें चीफ जस्टिस होंगे। उल्लेखनीय है कि नैनीताल हाईकोर्ट का गठन 9 नवम्बर 2000 में राज्य गठन के साथ ही किया गया था तथा अशोक ए देसाई को नैनीताल हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। जिनका कार्यकाल महज 26 दिन का रहा था। तब से लेकर अब तक नैनीताल हाईकोर्ट में 10 चीफ जस्टिस नियुक्त किये जा चुके हैं। वर्तमान में रमेश रांगनाथन चीफ जस्टिस पद पर आसीन हैं तथा 11 वें चीफ जस्टिस के रूप में अब इस पद पर आर.बी. मल्लिक की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गयी है।

नई तकनीकों का इस्तेमाल कर युवा निभाएं महत्वपूर्ण भूमिका

शुभारम्भ

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आईटी पार्क, दून में इण्डिया ड्रोन फेस्टिवल-2.0 का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने विभाग को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ने एनटीआरओ के सहयोग से इस क्षेत्र में बहुत कम समय में काफी प्रगति की है। आज के तकनीकी युग में ड्रोन का बहुआयामी उपयोग हो सकता है। उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं

मुख्यमंत्री ने किया 'इण्डिया ड्रोन फेस्टिवल-2.0' का शुभारम्भ

उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है



इण्डिया ड्रोन फेस्टिवल-2.0' के शुभारम्भ अवसर पर सीएम व अन्य।

को देश का भविष्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देहरादून में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस प्रकार की नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए

युवा अपने देश व प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ड्रोन व इससे सम्बन्धित तकनीकी शिक्षा से युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के मेरी सरकार शुभारम्भ किया। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे सरकार से सम्पर्क

कर किसी भी विषय में अपने सुझाव दे सकता है। मुख्यमंत्री ने जोआईएस बेस्ड, ड्रोन मैपर सॉफ्टवेयर का भी विमोचन किया। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से तैयार इस सॉफ्टवेयर के द्वारा फोटो को कैप्चर करने, 3डी मॉडल बनाने एवं डाटा विश्लेषण करने में किया जा सकेगा। सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि इण्डिया ड्रोन फेस्टिवल 2.0 को प्रदेश के 13 जनपदों के 1500 स्कूल एवं लगभग 2 लाख बच्चे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने ड्रोन की उपयोगिता को समझाते हुए कहा कि यह प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में आपातकालीन परिस्थितियों में काफी सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, विधायक गणेश जोशी, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा भी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली एम्स में भर्ती साध्वी पद्मावती की हालत में नहीं हुआ कोई सुधार
(संवाददाता) देहरादून। हरिद्वार में गंगा रक्षा के लिए अनशन करते समय तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती मातृ सदन की साध्वी पद्मावती की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। दो दिन बाद भी अभी तक वे बेहोश ही हैं। हालांकि उनकी एमआरआई और सिटी स्कैन रिपोर्ट सामान्य हैं।

उपप्रधानों के चुनाव 26 फरवरी को

(संवाददाता) देहरादून। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि जनपद की 401 ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों के पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हैं। नाम निर्देशन से लेकर परिणाम की घोषणा तक के समस्त कार्य 26 फरवरी को सम्पन्न कराया जाना हैं।

सिंचाई विभाग में करोड़ों के कार्यों में घोटाले की सीबीआई जांच हो

(संवाददाता) देहरादून। महाकुंभ योजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपये के कार्यों में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए कांग्रेस ने मुख्यसचिव से की मांग की है। महाकुंभ 2021 हरिद्वार के अंतर्गत सिंचाई विभाग उत्तराखंड के कांठ पटरी मार्ग के पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की निविदाएं नियम विरुद्ध अपात्र लोगों को आवंटित किए जाने के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।

विद्याधर रतूड़ी के निधन पर शोक देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने टिहरी के प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी विद्याधर रतूड़ी के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है।

सड़क सुरक्षा के उपायों के कार्य को भी स्वीकृति दी

बैठक

मुख्य सचिव ने ली सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्ध समिति की बैठक

देहरादून। **संवाददाता**

सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्ध समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन शैलेश बगोली को सड़क सुरक्षा कोष के अन्तर्गत परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग एवं शिक्षा के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से प्रस्ताव लेकर तदानुसार बजट



मुख्य सचिव सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्ध समिति की बैठक लेते हुए।

स्वीकृति कराने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 के तहत कोष से स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत किये गये भौतिक कार्यों की समीक्षा की तथा शिक्षा विभाग

द्वारा प्रस्तावित चित्रांकन प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु स्वीकृत 7.23 लाख रुपये शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये। अपर निदेशक शिक्षा द्वारा बताया गया कि स्वीकृत योजनानुसार शिक्षा विभाग द्वारा

अपने संसाधन से अब तक प्रशिक्षण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा घनशाली-तिलबाड़ा मोटर मार्ग (राजमार्ग सं015) कि0मी0 19 से 51 कि0मी0 के मध्य संभावित दुर्घटना क्षेत्रों में क्रैश बैरियर व पैराफिट लगाने के 68.14 लाख लागत के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। ज्ञातव्य है कि यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल है। इसी क्रम में मुख्य सचिव ने 8.86 लाख की लागत के जनपद चम्पावत के लोहाघाट बाड़ाकोट सिमलखेत काफलीखान भनौली मोटर मार्ग (राज्य मार्ग 57) में सड़क सुरक्षा के उपायों के कार्य को भी स्वीकृति दी।

आयोग की परीक्षाओं को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पादित करने के लिए निर्देश

(संवाददाता) देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को आयोग की परीक्षाओं को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर उसकी व्यापक स्तर पर जांच की जाए तथा जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराये जाने की भी प्रभावी व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया को बाधित करने वालों को किसी भी स्तर पर बक्शा नहीं जायेगा।

टिहरी बांध परियोजना सीबीआईपी अवार्ड से सम्मानित

संवाददाता देहरादून। टिहरी बांध परियोजना को हाइड्रो पावर सेक्टर में बेस्ट परफॉरमिंग यूटिलिटी अवार्ड-2020 से सीबीआईपी (सेंटल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एंड पावर) द्वारा सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जल संसाधन राज्य मंत्री, भारत सरकार रतन लाल कटारिया द्वारा डी.वी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टीएचडीसीआईएल को स्कोप कंवेशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर राजीव विश्वासी, निदेशक (तकनीकी) सहित मुहर मणि, कार्यपालक निदेशक, यू.सी. कन्नोजिया, महाप्रबन्धक (एनसीआर) तथा सजीव आर, महाप्रबन्धक (ओ.एंड.एम.) भी उपस्थित रहे।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+



Scan This Code

Read News
Watch News Channel



स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के. प्रिंटर्स, 74/9, आराधर, देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०-
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं०
UTTHIN/2005/15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।